



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937

No. 276]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी/एल. ए. डी. - एन. आर. ओ. / जी. एन/ 2015-16/008.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में,-
 - विनियम 60 में, उप-विनियम (3) के पश्चात् और उप-विनियम (4) से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु यह कि इस उप-विनियम की अपेक्षाएँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) के उत्पाद (प्रोडक्ट) संबंधी विज्ञापनों के मामले में लागू नहीं होंगी।"
 - अध्याय X के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् :-

"अध्याय X**संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्ट्र्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्धता****लागू होना**

106ब. (1) इस अध्याय के उपबंध (प्रावधान) उन एंटिटियों पर लागू होंगे जो केवल संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्ट्र्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर, या तो सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के अनुसरण में या अन्यथा, अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) चाहती हों।

(2) इन विनियमों के उपबंध (प्रावधान), उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से विवेचन न किया गया हो (जिनका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो) या जो इस अध्याय के अधीन अपवर्जित हैं (शामिल नहीं

हैं), यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की किसी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के प्रति लागू होंगे:

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (4), विनियम 26 के उप-विनियम (1) तथा (2) के उपबंध (प्रावधान) इस अध्याय के अधीन कराई गई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के प्रति लागू नहीं होंगे।

(3) संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) तक संस्थागत निवेशक (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) और गैर संस्थागत निवेशक (नॉन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) पहुँच रख सकेंगे।

परिभाषाएँ

106भ. (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म" (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) से उन एंटिटियों की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) और उनके व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु व्यापारिक प्लेटफार्म अभिप्रेत है, जो विनियम 106म में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती हों;

(ख) "संस्थागत निवेशक" (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) से अभिप्रेत है:

(i) अर्हित संस्थागत क्रेता (क्वैलीफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर); या

(ii) कौटुंबिक न्यास (फैमिली ट्रस्ट) या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से (सिस्टमिकली) महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ या बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी), जिन सभी की शुद्ध-मालियत (नेट-वर्थ), अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक हो;

(ग) "सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2(1)(थ) के अधीन इसके लिए नियत है।

(2) इस अध्याय में उपयोग किए गए किंतु उप-विनियम (1) के अधीन अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों का अर्थ इन विनियमों के विनियम 2 से लिया जाएगा।

पात्रता

106म. (1) निम्नलिखित एंटिटियाँ संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए पात्र होंगी,-

(क) कोई एंटिटी जो उत्पादों (प्रोडक्ट्स), सेवाओं या कारबार के प्लेटफार्म (बिजनेस प्लेटफार्म) को बेहतरीन रूप में प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी), सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), बौद्धिक संपदा (इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी), डाटा एनालिटिक्स, बायो-टेक्नोलॉजी या नैनो-टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग करती हो, और उसकी निर्गम से पूर्व की पूँजी का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, बोर्ड के पास, यथास्थिति, प्रारूप सूचना दस्तावेज (ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) या प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख को, अर्हित संस्थागत क्रेता (क्रेताओं) (क्वैलीफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर) द्वारा धारित हो; या

(ख) कोई अन्य एंटिटी, जिसमें निर्गम से पूर्व की पूँजी का कम से कम पचास प्रतिशत, बोर्ड के पास, यथास्थिति, प्रारूप सूचना दस्तावेज या प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख को, अर्हित संस्थागत क्रेताओं द्वारा धारित हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, अकेले या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से, उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट एंटिटी में निर्गम के पश्चात् की शेयर पूँजी का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक धारण नहीं करेगा।

सार्वजनिक निर्गम के बिना सूचीबद्धता

106य. (1) सार्वजनिक निर्गम लाए बिना अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता चाहने वाली एंटीटी इन विनियमों के अनुसार बोर्ड के पास प्रारूप सूचना दस्तावेज (ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डोक्यूमेंट) आवश्यक दस्तावेजों के साथ और इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ दाखिल करेगी।

(2) प्रारूप सूचना दस्तावेज के अंतर्गत इन विनियमों में प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डोक्यूमेंट) के लिए यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) सम्मिलित होंगे।

(3) निम्नलिखित से संबंधित विनियम सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के बिना सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के मामले में लागू नहीं होंगे:

- (i) आबंटन (अलॉटमेंट) से संबंधित;
- (ii) निर्गम (इश्यू) के खुलने / बंद होने से संबंधित;
- (iii) विज्ञापन से संबंधित;
- (iv) हामीदारी से संबंधित;
- (v) विनियम 26 के उप-विनियम (5) से संबंधित;
- (vi) कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग) से संबंधित;
- (vii) निर्गम (इश्यू) संबंधी सामग्री के प्रेषण से संबंधित;
- (viii) और जनता को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के प्रस्ताव से संबंधित ऐसे अन्य उपबंध (प्रावधान)।

(4) एंटीटी उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्रास करेगी जहाँ उसका अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव हो।

(5) एंटीटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को:

- (क) बोर्ड द्वारा टिप्पणियाँ (संप्रेक्षण) जारी किए जाने की तारीख से; या
- (ख) विनियम 6 के उप-विनियम (2) में नियत अवधि (कालावधि) की समाप्ति से, यदि बोर्ड ने ऐसी कोई टिप्पणी (संप्रेक्षण) जारी न की हों।

तीस दिनों के भीतर सूचीबद्ध कराएगी:

(6) जिस एंटीटी को सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए बिना, संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ हो, उस एंटीटी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म पर सूचीबद्धता के सीमित प्रयोजन हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) के खंड (ख) की अपेक्षा से नियम 19 के उप-नियम (7) के अधीन बोर्ड द्वारा अधित्यजित किया गया है।

(7) न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से संबंधित उपबंध (प्रावधान) उन एंटीटियों पर लागू नहीं होंगे जो सार्वजनिक निर्गम लाए बिना संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

(8) प्रारूप और अंतिम सूचना दस्तावेज को एंटीटी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और जिस पर सभी निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अर्थात्, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर प्रबंध निदेशक या प्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, अर्थात्, पूर्णकालिक वित्त निदेशक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जो वित्त-संबंधी कृत्य का प्रमुख हो तथा उस कृत्य का निर्वहन कर रहा हो।

(9) हस्ताक्षरकर्ता यह भी प्रमाणित करेंगे कि सूचना दस्तावेज में किए गए सभी प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) सत्य और सही हैं।

(10) सूचना दस्तावेज में मिथ्या कथन या उसके अंतर्गत किसी लोप के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार दायी होगा, जिसने सूचना दस्तावेज को जारी करना प्राधिकृत किया हो।

सार्वजनिक निर्गम के अनुसरण में सूचीबद्धता

106यक. (1) अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम और उनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) चाहने वाली एंटीटी इन विनियमों के अनुसार बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट), आवश्यक दस्तावेजों के साथ और इन विनियमों की अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ दाखिल करेगी।

(2) न्यूनतम आवेदन आकार दस लाख रुपये का होगा।

(3) आबंटितियों (अलॉटी) की संख्या दो सौ से अधिक होगी।

(4) जनता को शुद्ध प्रस्ताव संबंधी प्रवर्ग में आबंटन निम्नानुसार होगा:

(a) संस्थागत निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को पचहत्तर प्रतिशत:

परंतु यह कि एंकर निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के लिए अलग से कोई भी आबंटन नहीं होगा;

(b) गैर-संस्थागत निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को पच्चीस प्रतिशत;

(5) गैर-संस्थागत निवेशक संबंधी प्रवर्ग में कोई अल्प-अभिदान (अंडर-सब्सक्रिप्शन) संस्थागत निवेशकों के प्रवर्ग के अंतर्गत अभिदान के लिए उपलब्ध होगा।

(6) संस्थागत निवेशकों को आबंटन विवेक के आधार पर हो सकेगा, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों को आबंटन आनुपातिक आधार पर होगा।

(7) संस्थागत निवेशकों को आबंटन करने की रीति (का तरीका) (अर्थात्, विवेक के आधार पर या आनुपातिक आधार पर) प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पूर्व या दाखिल करने के समय प्रकट की जाएगी।

(8) संस्थागत निवेशकों को विवेक के आधार पर आबंटन करने के मामले में, किसी भी संस्थागत निवेशक को निर्गम के आकार का दस प्रतिशत से अधिक आबंटित नहीं किया जाएगा।

(9) प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गम के व्यापक उद्देश्य प्रकट किए जाएंगे।

(10) निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) के आधार में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) सम्मिलित हो सकेंगे, अनुमानों (प्रोजेक्शन) को छोड़कर, जैसा निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) द्वारा ठीक समझा जाए, ताकि निवेशक सोच-समझकर निर्णय (विनिश्चय) लेने में समर्थ हो सकें और प्रकटीकरणों के जरिए मूल्यांकन के आधार की पूरी-पूरी जानकारी देते हुए निवेशकों को आगाह किया जाएगा।

अवरुद्धता (लॉक-इन)

106यख. (1) शेयरधारकों की निर्गम से पूर्व की पूरी पूँजी सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के अनुसरण में सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के मामले में आबंटन की तारीख से या सार्वजनिक निर्गम के बिना सूचीबद्धता के मामले में सूचीबद्धता की तारीख से छह महीनों की अवधि के लिए रुद्ध (लॉकड-इन) हो जाएगी:

परंतु यह कि इस विनियम में दी हुई कोई भी बात:

(i) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले एंटीटी की कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अधीन कर्मचारियों को आबंटित किए गए इक्विटी शेयरों पर लागू नहीं होगी, यदि एंटीटी ने अनुसूची VIII के भाग-क के अनुसार ऐसे विकल्पों या स्कीम के संबंध में पूरे प्रकटीकरण कर दिए हों;

(ii) जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड) या प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश (विनिधान) निधि (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर लागू नहीं होगी:

परंतु यह कि ऐसे इक्विटी शेयर जोखिम पूँजी निधि या आनुकल्पिक निवेश निधि या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक द्वारा क्रय की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए रुद्ध (लॉक-इन) हो जाएंगे।

(iii) सार्वजनिक निर्गम के बिना सूचीबद्धता के मामले में सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व की अवधि तक लगातार, संप्रवर्तकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर लागू नहीं होगी:

स्पष्टीकरण.- खंड (ii) एवं (iii) के प्रयोजनार्थ, यदि ऐसे इक्विटी शेयर पूर्णतः समादत्त (पेड-अप) अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन के अनुसरण में परिणामित हुए (इक्विटी शेयर बने) हों, तो एक वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ ऐसी संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को धारण किए जाने की अवधि (होलिडिंग पीरियड) के साथ-साथ पारिणामिक इक्विटी शेयरों को धारण किए जाने की अवधि (होलिडिंग पीरियड) पर विचार किया जाएगा और संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को पूर्णतः समादत्त (पेड-अप) समझा जाएगा, यदि उन पर देय पूरा प्रतिफल (कन्सिडरेशन) उनके संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) के समय अदा कर दिया गया हो।

(2) संप्रवर्तकों द्वारा धारित तथा रुद्ध (लॉकड-इन) विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंक या लोक वित्तीय संस्था के पास, संपाश्विक जमानत (संपाश्विक प्रतिभूति / कलैटरल सिक्यूरिटी) के रूप में ऐसे बैंक या संस्था द्वारा दिए गए ऋण (लोन) हेतु गिरवी रखा जा सकेगा, यदि विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को गिरवी रखना ऋण (लोन) की मंजूरी की शर्तों में से एक शर्त हो।

(3) जो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ रुद्ध (लॉकड-इन) हों, वे विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ इन विनियमों के विनियम 40 के अनुसार अंतरणीय (ट्रांसफरेबल) हो सकेंगी।

(4) विवेक के (वैवेकिक) आधार पर आबंटित की गई सभी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) में एंकर निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) द्वारा अवरुद्धता (लॉकड-इन) संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार रुद्ध (लॉकड-इन) किया जाएगा, जैसा अनुसूची XI के भाग क में खंड 10(ज) के अधीन विनिर्दिष्ट हो।

व्यापारिक लॉट (ट्रेडिंग लॉट)

106यग. न्यूनतम व्यापारिक लॉट (ट्रेडिंग लॉट) दस लाख रुपये का होगा।

सार्वजनिक निर्गम लाए बिना सूचीबद्ध एंटीटियों का निकास (एग्जिट)

106यच. (1) जिस एंटीटी की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ सार्वजनिक निर्गम लाए बिना संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हों, वह एंटीटी उस प्लेटफार्म से निकास (एग्जिट) कर सकेगी, यदि-

(क) उसके शेयरधारक डाक मतपत्र (पोस्टल वॉलेट) के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करके ऐसे निकास (एग्जिट) को अनुमोदित कर देते हों जहाँ कुल मतों में से नब्बे प्रतिशत मत और गैर-संप्रवर्तकों के बहुसंख्यक मत ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए हों; और

(ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध हों, ऐसे निकास को अनुमोदित कर देता हो।

(2) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक निर्गम लाए बिना सूचीबद्ध एंटीटी की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उसी प्रकार असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर सकेगा, जैसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन असूचीबद्ध एंटीटी के संप्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा संप्रवर्तित किसी भी एंटीटी को, ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि हेतु संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध किए जाने की अनुज्ञा (अनुमति) नहीं दी जाएगी:

परंतु यह कि इस विनियम के उपबंध (प्रावधान) ऐसी असूचीबद्ध एंटीटी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा संप्रवर्तित किसी दूसरी एंटीटी पर लागू नहीं होंगे।

मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) में स्थानांतरण (माइग्रेशन)

106यड. जिस एंटीटी ने इस अध्याय के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराई हों, वह एंटीटी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) में, स्टॉक एक्सचेंज की पात्रता संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्वधीन, स्थानांतरित (माइग्रेट) होने का विकल्प चुन सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

106यच. लघु एवं मध्यम उद्यमों, जो संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध हों, के प्रति, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम,

2015 के प्रारंभ की तारीख को, यथा लागू अध्याय Xg के और बोर्ड द्वारा जारी सभी निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स), अनुदेशों या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधान (उपबंध), उस अवधि तक, जब तक ऐसी कंपनियाँ संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध रहें या उस समय तक जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेंगे, मानो कि अध्याय Xg निरसित ही न हुआ हो।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के अधीन, पद 'निर्गम से पूर्व' और 'निर्गम के पश्चात्', जहाँ कहीं भी वे आते हों, के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे, सार्वजनिक निर्गम के बिना सूचीबद्धता की दशा में, क्रमशः 'सूचीबद्धता से पूर्व' और 'सूचीबद्धता के पश्चात्' के संदर्भ में हैं।

(iii) अनुसूची IV में,-

(क) संदर्भ वाले शीर्षक में, शब्द, संख्याएँ और चिह्नों "तथा 91ड(3)", शब्द, संख्याओं और चिह्नों ", 91ड(3), 106य(1) तथा 106यक(1)" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

(ख) भाग क में, पैरा (1) में, उप-पैरा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ग) सार्वजनिक निर्गम के बिना सूचीबद्धता के मामले में:

एंटीटी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)	फीस की राशि / दर
दस करोड़ रुपये से कम या के बराबर	एक लाख रुपये (₹1,00,000/-) का सपाट प्रभार (फ्लैट चार्ज)।
दस करोड़ रुपये से अधिक, किंतु पाँच हजार करोड़ रुपये से कम या के बराबर	समादत्त पूँजी का 0.1 प्रतिशत।
पाँच हजार करोड़ रुपये से अधिक	पाँच करोड़ रुपये (₹5,00,00,000/-) और पाँच हजार करोड़ रुपये (₹5000,00,00,000/-) से अधिक की समादत्त पूँजी के हिस्से का 0.025 प्रतिशत।

(iv) अनुसूची VI में, प्ररूप क में, खंड 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(18) हम यह प्रमाणित करते हैं कि एंटीटी इन विनियमों के अध्याय Xg के अधीन संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के लिए 106म (1) (क) या (ख) (यथास्थिति) के अधीन पात्र है। (यदि लागू हो)"

(v) अनुसूची VIII में,-

(क) भाग क से पूर्व उल्लिखित शब्द "शब्द "समूह कंपनियाँ" जहाँ कहीं भी आये, से निर्गमकर्ताओं के संप्रवर्तकों द्वारा संप्रवर्तित कंपनियाँ, फर्म, उद्यम इत्यादि अभिप्रेत हैं, इसका विचार किये बिना कि ये सत्ताएँ (एंटीटी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1) (ख) के अंतर्गत आती हैं या नहीं" निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात् :-

"(i) शब्दों "समूह कंपनियाँ", जहाँ कहीं भी वे आते हों, में ऐसी कंपनियाँ सम्मिलित होंगी जो लागू लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) के अंतर्गत आती हों और उनमें अन्य कंपनियाँ भी सम्मिलित होंगी जो निर्गमकर्ता के बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण (तात्विक) समझी जाएँ।

(ii) महत्ता (तात्विकता) संबंधी नीति को प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जाएगा।"

(ख) भाग क में, पैरा (2) में, उप-पैरा (X) में, खंड (क) में,-

(I) उप-खंड (1) एवं (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात् :-

"(1) मुकदमे जिनमें निर्गमकर्ता / उसके निदेशक / संप्रवर्तक / उसकी समूह कंपनियाँ / समनुपंगियाँ (सन्सीडियरी) शामिल हों :

- (i) सभी दांडिक कार्यवाहियाँ ;
- (ii) कानूनी / विनियामक प्राधिकरणों द्वारा सभी कार्रवाइयाँ;
- (iii) कराधान – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित दावों के संबंध में पृथक् प्रकटीकरण, मामलों की संख्या और कुल रकम के ब्यौरे देते हुए समेकित रूप में ;
- (iv) अन्य लंबित मुकदमे - निर्गमकर्ता के बोर्ड द्वारा निर्धारित और प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट की गई महत्ता (तात्त्विकता) नीति के अनुसार ।

(2) लेनदारों के प्रति बकाया देयराशियाँ:

- (i) निर्गमकर्ता के बोर्ड की और प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट की गई महत्ता (तात्त्विकता) नीति के आधार पर, ऐसे लेनदारों के लिए प्रकटीकरण;
- (ii) लघु उपक्रमों और अन्य लेनदारों के प्रति बकाया देयराशियों के संबंध में समेकित जानकारी, मामलों की संख्या और निहित रकम के ब्यौरे अलग से देते हुए ;
- (iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अनुसार लेनदारों के प्रति बकाया देयराशियों के बारे में पूरे ब्यौरे कंपनी के वेबपेज पर प्रकट किए जाएँगे और साथ ही उनका वेब-लिंक भी प्रस्ताव दस्तावेज में दिया जाएगा ।"

(II) उप-खंड (3) का लोप हो जाएगा ।

(vi) अनुसूची XIXक का लोप हो जाएगा ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69 जैड बी/15 (165)]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 द्वारा, 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्श्चात् :-
 - (1) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/ 186926, द्वारा
 - (2) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/ 25/189240, द्वारा
 - (3) 8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा
 - (4) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा
 - (5) 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा

- (6) 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/05/13907, द्वारा
- (7) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/24/30181, द्वारा
- (8) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2011-12/25/30309, द्वारा
- (9) 30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/ 2499, द्वारा
- (10) 7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/35/3186, द्वारा
- (11) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/04/11262, द्वारा
- (12) 24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/12/18951, द्वारा
- (13) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/18/5391, द्वारा
- (14) 27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/ 32/4947, द्वारा
- (15) 26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी-एन/ 2013-2014/19/6422, द्वारा
- (16) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/ 28/6720, द्वारा
- (17) 7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2013-14/36/12, द्वारा
- (18) 4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/ 44/226, द्वारा
- (19) 23 मई 2014 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (20) 25 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./ 2014-15/06/1372, द्वारा
- (21) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/ 24/538, द्वारा
- (22) 5 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./ जी.एन./2015-16/003, द्वारा

- 23) 11 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/007, द्वारा संशोधित हुए थे

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th August, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2015

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/008.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, -
 - (i) in regulation 60, after sub-regulation (3) and before sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that requirements of this sub-regulation shall not be applicable in case of product advertisements of the issuer.” (ii) for Chapter XC, the following shall be substituted, namely:-

“CHAPTER XC

LISTING ON INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM

Applicability.

106W. (1) The provisions of this chapter shall apply to entities which seek listing of their specified securities exclusively on the institutional trading platform either pursuant to a public issue or otherwise.

(2) The provisions of these regulations, in respect of the matters not specifically dealt or excluded under this Chapter, shall apply *mutatis mutandis* to any listing of specified securities under this Chapter:

Provided that the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, sub-regulations (1) and (2) of regulation 26 of these regulations shall not apply to listing of specified securities made under this Chapter.

(3) The institutional trading platform shall be accessible to institutional investors and non-institutional investors.

Definitions.

106X. (1) In this chapter, unless the context otherwise requires,-

- (a) “institutional trading platform” means the trading platform for listing and trading of specified securities of entities that comply with the eligibility criteria specified in regulation 106Y;
 - (b) “institutional investor” means:
 - (i) qualified institutional buyer; or
 - (ii) family trust or systematically important NBFCs registered with Reserve Bank of India or intermediaries registered with the Board, all with net-worth of more than five hundred crore rupees, as per the last audited financial statements;
 - (c) “persons acting in concert” shall have the same meaning as assigned to it under regulation 2(1)(q) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.
- (2) All other words and expressions used in this Chapter but not defined under sub-regulation (1) shall derive their meaning from regulation 2 of these regulations.

Eligibility.

106Y. (1) The following entities shall be eligible for listing on the institutional trading platform,-

- (a) an entity which is intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, bio-technology or nano-technology to provide products, services or business platforms with

substantial value addition and at least twenty five per cent of its pre-issue capital is held by qualified institutional buyer(s) as on the date of filing of draft information document or draft offer document with the Board, as the case may be; or

(b) any other entity in which at least fifty per cent of the pre-issue capital is held by qualified institutional buyers as on the date of filing of draft information document or draft offer document with the Board, as the case may be.

(2) No person, individually or collectively with persons acting in concert, shall hold twenty five per cent or more of the post-issue share capital in an entity specified in sub-regulation (1).

Listing without public issue.

106Z. (1) An entity seeking listing of its specified securities without making a public issue shall file a draft information document along with necessary documents with the Board in accordance with these regulations along with fee as specified in Schedule IV of these regulations.

(2) The draft information document shall contain the disclosures as specified for draft offer document in these regulations.

(3) Regulations relating to the following shall not be applicable in case of listing without public issue:

- (i) allotment;
- (ii) issue opening / closing;
- (iii) advertisement;
- (iv) underwriting;
- (v) sub-regulation (5) of regulation 26;
- (vi) pricing;
- (vii) dispatch of issue material;
- (viii) and other such provisions related to offer of specified securities to public.

(4) The entity shall obtain in-principle approval from the 10ecognized stock exchanges on which it proposes to get its specified securities listed.

(5) The entity shall list its specified securities on the 10ecognized stock exchange(s) within thirty days:

- (a) from the date of issuance of observations by the Board; or
- (b) from the expiry of the period stipulated in sub-regulation (2) of regulation 6, if the Board has not issued any such observations.

(6) The entity which has received in-principle approval from the recognized stock exchange for listing of its specified securities on the institutional trading platform, without making a public issue, shall be deemed to have been waived by the Board under sub-rule (7) of rule 19 from the requirement of clause (b) of sub-rule (2) of rule 19 of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 for the limited purpose of listing on the institutional trading platform.

(7) Provisions relating to minimum public shareholding shall not apply to entities listed on institutional trading platform without making a public issue.

(8) The draft and final information document shall be approved by the board of directors of the entity and shall be signed by all directors, the Chief Executive Officer, i.e., the Managing Director or Manager within the meaning of the Companies Act, 2013 and the Chief Financial Officer, i.e., the Whole-time Finance Director or any other person heading the finance function and discharging that function.

(9) The signatories shall also certify that all disclosures made in the information document are true and correct.

(10) In case of mis-statement in the information document or any omission therein, any person who has authorized the issue of information document shall be liable in accordance with the provisions of the SEBI Act, 1992 and regulations made thereunder.

Listing pursuant to public issue.

106ZA. (1) An entity seeking issue and listing of its specified securities shall file a draft offer document along with necessary documents with the Board in accordance with these regulations along with fees as specified in Schedule IV of these regulations.

(2) The minimum application size shall be ten lakh rupees.

(3) The number of allottees shall be more than two hundred.

(4) The allocation in the net offer to public category shall be as follows:

- (a) seventy-five per cent to institutional investors:
Provided that there shall be no separate allocation for Anchor Investors;
- (b) twenty-five per cent to non-institutional investors;
- (5) Any under-subscription in the non-institutional investor category shall be available for subscription under the institutional investors' category.

- (6) The allotment to institutional investors may be on a discretionary basis whereas the allotment to non-institutional investors shall be on a proportionate basis.
- (7) The mode of allotment to institutional investors, i.e., whether discretionary or proportionate, shall be disclosed prior to or at the time of filing of the Red Herring Prospectus.
- (8) In case of discretionary allotment to institutional investors, no institutional investor shall be allotted more than ten per cent of the issue size.
- (9) The offer document shall disclose the broad objects of the issue.
- (10) The basis of issue price may include disclosures, except projections, as deemed fit by the issuers in order to enable investors to take informed decisions and the disclosures shall suitably caution the investors about basis of valuation.

Lock-in.

106ZB. (1) The entire pre-issue capital of the shareholders shall be locked-in for a period of six months from the date of allotment in case of listing pursuant to public issue or date of listing in case of listing without public issue:

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to:

- (i) equity shares allotted to employees under an employee stock option or employee stock purchase scheme of the entity prior to the initial public offer, if the entity has made full disclosures with respect to such options or scheme in accordance with Part A of Schedule VIII;
- (ii) equity shares held by a venture capital fund or alternative investment fund of Category I or a foreign venture capital investor:
Provided that such equity shares shall be locked in for a period of at least one year from the date of purchase by the venture capital fund or alternative investment fund or foreign venture capital investor.
- (iii) equity shares held by persons other than promoters, continuously for a period of at least one year prior to the date of listing in case of listing without public issue:

Explanation.- For the purpose of clause (ii) and (iii), in case such equity shares have resulted pursuant to conversion of fully paid-up compulsorily convertible securities, the holding period of such convertible securities as well as that of resultant equity shares together shall be considered for the purpose of calculation of one year period and the convertible securities shall be deemed to be fully paid-up, if the entire consideration payable thereon has been paid at the time of their conversion.

- (2) The specified securities held by promoters and locked-in may be pledged with any scheduled commercial bank or public financial institution as collateral security for loan granted by such bank or institution if the pledge of specified securities is one of the terms of sanction of the loan.
- (3) The specified securities that are locked-in may be transferable in accordance with regulation 40 of these regulations.
- (4) All specified securities allotted on a discretionary basis shall be locked-in in accordance with the requirements for lock-in by Anchor Investors on main board of the stock exchange, as specified under clause 10(j) in Part A of Schedule XI.

Trading lot.

106ZC. The minimum trading lot shall be ten lakh rupees.

Exit of entities listed without making a public issue.

106ZD. (1) An entity whose specified securities are listed on the institutional trading platform without making a public issue may exit from that platform, if-

- (a) its shareholders approve such exit by passing a special resolution through postal ballot where ninety per cent of the total votes and the majority of non-promoter votes have been cast in favor of such proposal; and
 - (b) the recognized stock exchange where its shares are listed approve of such an exit.
- (2) The recognized stock exchange may delist the specified securities of an entity listed without making a public issue upon non-compliance of the conditions of listing and in the manner as specified by the stock exchange.

(3) No entity promoted by promoters and directors of an entity delisted under sub-regulation (2), shall be permitted to list on institutional trading platform for a period of five years from the date of such delisting:

Provided that the provisions of this regulation shall not apply to another entity promoted by the independent directors of such a delisted entity.

Migration to main board.

106ZE. An entity that has listed its specified securities on a recognized stock exchange in accordance with the provisions of this Chapter may at its option migrate to the main board of that recognized stock exchange after expiry of three years from the date of listing subject to compliance with the eligibility requirements of the stock exchange.

Repeal and saving.

106ZF. The provisions of Chapter XC and all directions, guidelines, instructions or circulars, issued by the Board as applicable to small and medium enterprises which are listed on the institutional trading platform, as on the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 shall continue to remain in force for the period such companies are listed on the institutional trading platform or till such time as specified by the Board, whichever is earlier, as if Chapter XC had not been repealed.

Explanation.- Under this Chapter, the phrases ‘pre-issue’ and ‘post-issue’, wherever they occur shall be construed as ‘pre-listing’ and ‘post-listing’, respectively, in case of listing without public issue.

(iii) in Schedule IV,-

- (a) in reference title, the word, number and symbol “ and 91E(3)”, shall be substituted with the word, numbers and symbols “,91E(3), 106Z(1) and 106ZA(1)”;
- (b) in Part A, in para (1), after sub-para (b), the following shall be inserted, namely:-

(c) In case of listing without public issue:

Paid up capital of the entity	Amount / Rate of fees
Less than or equal to ten crore rupees.	A flat charge of one lakh rupees (₹1,00,000).
More than ten crore rupees, but less than or equal to five thousand crore rupees.	0.1 per cent of the paid up capital
More than five thousand crore rupees.	Five crore rupees (₹5,00,00,000) plus 0.025 percent of the portion of the paid up capital in excess of five thousand crore rupees (₹5000,00,00,000).

(iv) in Schedule VI, in Form A, after clause 17, the following shall be inserted, namely:-

“(18) We certify that the entity is eligible under 106Y (1) (a) or (b) (as the case may be) to list on the institutional trading platform, under Chapter XC of these regulations. (if applicable)”

(v) in Schedule VIII, -

(a) the recital before Part A, shall be substituted with the following, namely:-

“(i) The words “group companies”, wherever they occur, shall include such companies as covered under the applicable accounting standards and also other companies as considered material by the board of the issuer.

(ii) The policy on materiality shall be disclosed in the offer document.”

(b) in Part A, in para (2), in sub-para (X), in clause (A), -

(I) sub-clauses (1) and (2) shall be substituted with the following, namely:-

“(I) Litigations involving the issuer/ its directors/promoters/group companies/ subsidiaries:

- (i) All criminal proceedings;
- (ii) All actions by statutory / regulatory authorities;
- (iii) Taxation – Separate disclosures regarding claims related to direct and indirect taxes, in a consolidated manner giving details of number of cases and total amount;

- (iv) Other pending litigations – As per policy of materiality defined by the board of the issuer and disclosed in the offer document.
- (2) Outstanding dues to creditors:
 - (i) Based on the policy on materiality of the board of the issuer and as disclosed in the offer document, disclosure for such creditors;
 - (ii) Consolidated information on outstanding dues to small scale undertakings and other creditors, separately giving details of number of cases and amount involved;
 - (iii) Complete details about outstanding dues to creditors as per (i) and (ii) above shall be disclosed on the webpage of the company with a web link thereto in the offer document.”
- (II) sub-clause (3) shall be omitted.
- (vi) Schedule XIX A shall be omitted.

U.K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./69 ZB/15(165)]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/15/174471.
2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-
 - (1) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/23/186926.
 - (2) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 2010/25/189240.
 - (3) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2009- 10/26/190146.
 - (4) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/03/1104.
 - (5) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010- 11/19/26456.
 - (6) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011-12/05/13907.
 - (7) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
 - (8) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011- 12/25/30309.
 - (9) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.

- (10) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.
- (11) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
- (12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/12/18951.
- (13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.
- (14) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.
- (15) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.
- (16) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
- (17) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
- (18) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.
- (19) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (20) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.
- (21) 24th March 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.
- (22) 5th May 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. No.SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/003.
- (23) 11th August 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/007.